

प्रसङ्ग

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
राष्ट्रियसंस्कृतशाला

संवाँ में

निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल।

सामाजिक कल्याण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 15 फरवरी 2008

विषय— राजकीय सम्प्रेषण गृह, अलमोड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाद्वय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1737/शोक0/निर्माण/2006-07 दिनांक 11 अगस्त, 2007 को द्वारा राजकीय सम्प्रेशन गृह, अल्मोड़ा के गवन निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा पठित रु० 70.50 लाख के आगमन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त कुल रु० 67.24 लाख (रु० सठसठ लाख बीबीस हजार मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में रु० 33.62 लाख (रु० तीस लाख अंसठ हजार मात्र) की धनराशि बालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था पानीपत अभियन्त्रण तथा प्रबंध, अल्मोड़ा को उपलब्ध करायी जावेगी।
- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें सिद्धमूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तादोपरान्त ही आगमन की स्वीकृति मान्य होगी।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, दिना. प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- कार्य पर चलाना ही व्यय विन्यास जाय जितना स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।
- कार्य कराने से पूर्व समुचित औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को संपादित करना सुनिश्चित करें।
- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-गोति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि आवंटित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- जीपी0डब्ल्यू0 कानून 9 की शर्तों के अनुसार इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगमन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या ' 2047 / XI ' -2' (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगमन गठित करते समय कदाई से पालन किया जाय।

13. उक्त धनराशि का आहरण उतना ही किया जाएगा, जितना 31-3-05 तक व्यय हो सकेंगी तथा कार्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ही प्रारम्भ किया जाएगा।
14. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा। विलम्ब के कारण यदि आगमन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपनी निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक बन्दापि व्यय न किया जाए।
15. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय इनतमुस्तका में उल्लिखित प्रावधानों एवं बजट मैन्युअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य करार के समय टेंडर विशयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।
16. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समकक्षता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
17. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अद्यमुक्त की जाएगी।
18. तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित अंशितपूर्ण आगमन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।
19. अद्यमुक्त धनराशि का बजट मैन्युअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आद-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परियोजना-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-103-महिला कल्याण-06-किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण-" के मातृक मद-"24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
21. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 775(I) XXVII(3)/07 दिनांक : 07 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 107/XVII-02/2008-08(33)/2005 तददिनांकित।

प्रतिनिधि : निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
3. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एनओसी सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(आर० के० चौहान)
अनुसचिव।